सिविल सर्विसेज मिनर्वा

सामान्य अध्ययन

वर्ष 9, अंक 2, फरवरी, 2014 मूल्य : 50 रुपये

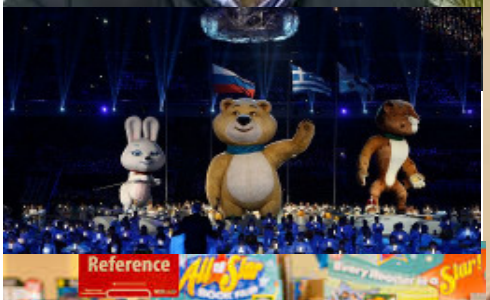

अनुक्रमणिका

राष्ट्रीय समसामयिकी

देश की पहली मोनोरेल का हुआ सफल ट्रायल 4
भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में प्रारम्भ किया गया 4
सिक्किम लोकायुक्त विधेयक 2014 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित 4
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का उद्घाटन किया 5
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समान अवसर आयोग की स्थापना की मंजूरी दी 5
आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 राज्यसभा में पारित 5
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िघ्या को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया 5

अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी

बेल्जियम में बच्चों को भी इच्छामृत्यु का अधिकार मिला 7
बच्चों के लिए इच्छामृत्यु की शर्तें 7
सुशील कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री निर्वाचित 7
युगांडा के राष्ट्रपति ने एंटी–गे बिल पर हस्ताक्षर किया 8
भारत और विष्व 9
भारत और कनाडा ने तीन समझौता–ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए 9
समझौते के मुख्य बिंदु 9

अर्थव्यवस्था/वाणिज्य

राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी 10

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण 11
पर्यावरण/पारिस्थितिकी 13
इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार–2010 13

पुरस्कार/सम्मान

अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 14
इजरायली राष्ट्रपति उत्कृष्टता पदक 14
राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2012–13 14
64वें बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 15

पुस्तकें

''लेवरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी इन साउथ एशिया'' 16
''हिंदू धर्म पर लिखी विवादास्पद वेंडी डोनीगर की किताब 'द हिंदूज : एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री'' 16
22वां विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न 17
पब्लिक ईश्यूज बिफोर पार्लियामेंट 17

सम्मेलन/समारोह

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के विदेश मंत्रियों की 35वीं बैठक 18
प्रेक्षक देश 18
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 18
संगठन के उद्देश्य 18
महासचिव 18
जी–20 समूह देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक सिडनी में संपन्न 19

पद्मत्याग/पद्मभुक्त

एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी 20
एन किरण कुमार रेड्डी 20
भारत के वयोवृद्ध सांसद रिशांग कीशिंग का राजनीति से संन्यास 20

निर्वाचित/नियुक्त

सत्य नडेला 22
मत्तेओ रेंजी 22
इब्राहीम महलाब 22
मत्तेओ रेंजी 22
ओलेक्जेंडर टर्चयोनोफ 23

निधन/मृत्यु

प्रोकाश करमाकर 24
रुद्र कृष्णा श्रीकान्तन 24

खेल/खिलाड़ी

2015 की विश्व ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार भारत को सौंपी गई 25
सोची ओलंपिक का समापन 25

Editorial and Corporate Office
Rajrooppur, Allahabad
RNI
UPHINDI/2005/26617
Publisher, Editor and Owner
Dheer Singh Rajput
Allahabad; Year 9, Issue 2, February, 2014
Place of Publication & Registerd Office
331è240 A, Stainly Road, Nayapura, Allahabad (UP)
Printing Press & Address
Academy Press Daraganj, Allahabad (UP)
Website : www.developindiagroup.com
E-mails : civilservicesminerva@gmail.com

संपादकीय और कॉरपोरेट ऑफिस
राजरूपपुर, इलाहाबाद
आरएनआई
UPHINDI/2005/26617
प्रकाशक, संपादक, और स्वामी
धीर सिंह राजपूत
इलाहाबाद, वर्ष 9, अंक 2, फरवरी, 2014
प्रकाशन का स्थान और रजिस्टर्ड ऑफिस
331/240 ए, स्टैनली रोड, नयापुरा, इलाहाबाद (उ.प्र.)
प्रिंटिग प्रेस का पता
एकेडमी प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद (उ.प्र.)
वेबसाइट : www.developindiagroup.com
ई–मेल : civilservicesminerva@gmail.com

Read

Only in 500/- per year

Develop India

http://www.developindiagroup.co.in/

Develop India

Only in 500/- per year

Online Subscription

http://www.developindiagroup.co.in/

राष्ट्रीय समसामयिकी

देश की पहली मोनोरेल का हुआ सफल ट्रायल

मुंबई में मोनो रेल का सफल ट्रायल रन किया गया। तीन डिब्बों वाली मोनोरेल वडाला से चौंबूर तक चलाई गई। इस यात्रा की अवधि 15 मिनट रही। देश की इस पहली मोनो रेल का ट्रायल देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुटी। एमएमआरडीए की इस परियोजना के तहत मुंबई के चेंबूर इलाके से वडाला तक पहली मोनो रेल आने वाले कुछ महीने में चलने लगेगी।

मोनोरेल परियोजना 2460 करोड़ रुपये की है। यह चेंबूर से वडाला तक की सवा आठ किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में तय करेगी। करीब 568 यात्रियों की क्षमता वाली मोनोरेल की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।

मुम्बई मोनोरेल भारतीय महानगर मुम्बई आधारित मोनोरेल निकाय है जो नगर में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए बनाया गया है। यह परियोजना मुम्बई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम मोनोरेल परियोजना है। इससे पूर्व कुण्डाला वैली रेलवे और पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रेनवेज 1920 में बन्द हो गये थे। इसका निर्माण कार्य जनवरी 2009 में आरम्भ हुआ और इसका प्रथम परिचालन रेखा का उद्घाटन 1 फरवरी 2014 को हुआ। मुम्बई मोनोरेल भारत की बहुप्रतीक्षित पहली मोनोरेल है। इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया। पहली मोनोरेल मुंबई के वडाला मोनो रेल डिपो से दोपहर 3 बजकर 57 मिनट पर चली और लगभग 15 मिनट का सफर तय करके 4 बजकर 12 मिनट पर चेंबूर पहुंची। 2 फरवरी 2014 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया।

मोनोरेल के आसमानी नीले, गुलाबी और हरे रंग के हर कोच में 20 यात्रियों के बैठने की जगह है जबकि अधिकतम 568 यात्री ट्रैवेल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्मों की न्यूनतम ऊंचाई करीब 5.5 मीटर है। अपने ट्रैक पर आने वाले मोड़ के दौरान 40 डिग्री तक झुक जाती है जिससे इसकी यात्रा के आरामदेह रहने पर प्रश्नचिह्न भी लगाए जा रहे हैं।

मोनोरेल अर्थात एकरेल एक परिवहन प्रणाली है जो केवल एक रेल पर चलती है। प्रायः यह एकल रेलपथ जमीन से कुछ उंचाई पर बनाया गया होता है।

- विश्व की पहली मोनोरेल 1820 में रूस के ईवान इलमानोव के द्वारा बेहतर यातायात के विकल्प्प के तौर पर बनाई गयी थी।
- 1821 में मोनोरेल का पहला ट्रायल दक्षिणी लंदन के डप्टफोर्ड डॉकयार्ड के हार्डफोर शेयर से रिवर ली तक किया गया था।
- 1900 में गायरोमोनोरेल का परीक्षण किया गया। 1901 में इसका लिवरपूल से मैनचेस्ट्टर के बीच प्रयोग भी किया गया।
- 1910 में गायरोमोनोरेल का प्रयोग अलास्का की खानों में कुछ समय तक किया गया।
- 1980 के बाद शहरीकरण के बढ़ने के साथ साथ ही जापान और मलेशिया में इसका बेहतर इस्तेमाल किया गया। आज टोकियो मोनोरेल विश्व का सबसे व्यस्त नेटवर्क है, जिसका प्रयोग हर रोज एक लाख सत्ताइस हजार यात्री करते हैं।

भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में प्रारम्भ किया गया

भारत की सबसे बड़ी, 130 मेगावाट की वेलस्पन सौर एमपी परियोजना 26 फरवरी 2014 को मध्य प्रदेश के नीमच के भगवानपुर में शुरू की गई. वेलस्पन सौर एमपी परियोजना 305 हेक्टेयर भूमि पर 1100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की गई थी. यह 8.05 रुपये प्रति किलोवाट की दर से बिजली की सप्लाई करेगी.

यह परियोजना भारत की सौर क्षमता को 7 प्रतिशत तक बढ़ाएगी.

केंद्र सरकार ने 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की शुरुआत की थी. भारत के पास 2208 मेगावाट ग्रिड–कनेक्टेड सौर ऊर्जा क्षमता है. जेएनएनएसएम का उद्देश्य भारत को 2022 तक 20000 मेगावाट (या 20 गीगावाट) की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता तक पहुंचाना है.

भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन–लागत हाल के वर्षों में आधे से भी ज्यादा घटी है. वह तीन वर्ष पहले के 17 रुपये प्रति किलोवाट–घंटे से घटकर 7.50 रुपये प्रति किलोवाट–घंटा रह गई है. पर यह लागत कोयले (2.50 रुपये रुपये प्रति किलोवाट–घंटा), न्यूक्लियर (3 रुपये प्रति किलोवाट–घंटा) या प्राकृतिक गैस (5.5 रुपये प्रति किलोवाट–घंटा) की तुलना में अभी भी ज्यादा है.

वेलस्पन ऊर्जा लिमिटेड (वेल) भारत में सोलर फोटोवोल्टेइक परियोजनाओं की सबसे बड़ी विकासकर्ता है. वेलस्पन ग्रुप की ऊर्जा शाखा एक स्वतंत्र ऊर्जा–उत्पादक है, जिसकी देशभर में ग्रिड कनेक्टेड 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 1 गीगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र निर्मित करने की योजना है.

ज्ञातव्य हो कि भारत अमेरिका के सहयोग से सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर पूरे देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपनी संभावना का आकलन कर रहा है.

सिक्किम लोकायुक्त विधेयक 2014 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित

सिक्किम राज्य की विधानसभा ने 26 फरवरी 2014 को सिक्किम लोकायुक्त विधेयक–2014 सर्वसम्मति से पारित किया. इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त शासन उपलब्ध कराना है. यह लोगों को मुख्यमंत्री से लेकर पंचायत तक और मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर करने की शक्ति प्रदान करता है.

सिक्किम लोकायुक्त विधेयक–2014 मुख्यमंत्री पवन चामलिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो राज्य के विधि विभाग के प्रभारी भी हैं. राज्यपाल श्रीनिवास पटेल की स्वीकृति मिलने पर यह बिल कानून बन जाएगा.

यह विधेयक केंद्रीय लोकपाल बिल पर आधारित है. इस विधेयक से सिक्किम के लोगों को फायदा होने की उम्मीद है, जो उन्हें शासन

और कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से लड़ने का मौका उपलब्ध कराएगा.

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का उद्घाटन किया

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंसदृ एनसीजीजी) का 24 फरवरी 2014 को उद्घाटन किया. एनसीजीएस देश में सुशासन सुधारों के लिए मार्गदर्शन और कार्यान्वयन का शीर्ष थिंकटैंक है.

नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीज) की स्थापना राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) मसूरी ने की. एनसीजीजी का प्रमुख कार्य सुशासन में अनुसंधानोन्मुख कार्रवाई पर होगा. यह केंद्र सरकार में सुशासन, ईदृ गवर्नेंस पहलों, प्रबंधन परिवर्तन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सूचनाओं के राष्ट्रीय भंडार के तौर पर काम करेगा.

एनसीजीजी प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों के हल, नीतियों और कार्यक्रम कार्यान्वयन के विश्लेषण, कार्ययोजना विकसित करने, प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों का समर्थन और विभिन्न क्षेत्रों, मंत्रालयों एवं विभागों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए काम करेगा.

एनसीजीजी की प्रतिक्रिया केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शोध पत्रों, प्रशासनिक सुधार, नीति विश्लेषण और महत्वपूर्ण निर्देशों वाले विकल्पों , मार्गदर्शन और प्रशासन में क्षमता निर्माण और प्रबंधन के मुद्दों पर होगी.

एनसीजीजी के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता शासकीय निकाय का गठन किया गया. इस सोसायटी के तहत आने वाले मामलों को शासी निकाय के समग्र अधीक्षण, निर्देशन के तहत प्रबंधित किया जाएगा. इसमें 12 सदस्यों वाली एक प्रबंधन समीति और अध्यक्ष के रूप में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव भी होंगे. इसकी संरचना तीन स्तर वाली होगी. पहले स्तर पर आंतरिक संकाय और सदस्य, दूसरे पर बाहर के घरेलू विशेषज्ञ और तीसरे स्तर पर अंतरराष्ट्रीय सलाहकार होंगे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समान अवसर आयोग की स्थापना की मंजूरी दी

20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समान अवसर आयोग (इक्वल ऑपर्चुनिटी कमिशनदृईओसी) की स्थापना को मंजूरी दी. ईओसी का प्रस्ताव भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर बनाई गई जस्टिस सच्चर समिति जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत आता है, की सिफारिशों पर की गई है.

समान अवसर आयोग अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सरकारी एजेंसियों द्वारा भेदभाव संबंधी शिकायतों का निपटारा करेगा. इसकी भूमिका सलाहकार की होगी और निजी एजेंसियां इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगीं. ईओसी में तीन सदस्य होंगें और उच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त जज इसके अध्यक्ष होंगें. इसके पास किसी भी प्रकार के दंड देने का अधिकार नहीं होगा.

- भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर बनाई गई जस्टिस सच्चर समिति की स्थापना मार्च 2005 में हुई थी.
- समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें यह लिखा गया था कि हालांकि देश की जनसंख्या में मुस्लिमों का प्रतिशत 18. 5 है फिर भी नौकरशाही में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही है.
- सच्चर समिति ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैरदृ राज्य एजेंसियों के खिलाफ की जाने वाली रोजाना की शिकायतों पर गौर नहीं कर सकती इसलिए वे समान अवसर आयोग (ईओसी) की सिफारिश कर रहे हैं.
- सच्चर समिति ने ईओसी की सिफारिश सभी लोगों के लिए की है.

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 राज्यसभा में पारित

राज्यसभा ने आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 (Andhra Pradesh Re-organisation Bill 2014) विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से 20 फरवरी 2014 को पारित किया. लोकसभा ने इस विधेयक को इससे पहले 18 फरवरी 2014 को ही पारित कर दिया था. इसका उद्देश्य भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन करना है.

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वाकआउट किया क्योंकि मत विभाजन की उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई. मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हालांकि वह विधेयक के प्रावधानों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है लेकिन वह तेलंगाना के लोगों के हित में इसे समर्थन दे रही है. भाजपा सहित विपक्षी दलों के संशोधन नामंजूर कर दिए गए. विधेयक का विरोध कर रहे तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने अपने संशोधनों पर जोर नहीं दिया.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसके लिए 6 सूत्रीय विकास पैकेज की घोषणा की जिसमें कर प्रोत्साहन सहित विशेष राज्य का दर्जा देना शामिल है. सीमांध्र में 13 जिले शामिल हैं. 6 सूत्रीय पैकेज सीमांध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए होगा.

प्रधानमंत्री ने सीमांध्र के 13 जिलों को पांच वर्ष के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा की. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन को आश्वासन दिया कि पुल्लावरम बहुउद्देश्यी परियोजना का काम केन्द्र करेगा और इस परियोजना के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए अगर और बदलावों की जरूरत पडी तो वे भी किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के बंटवारे के बाद सीमांध्र में संसाधनो की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए पहले एक वर्ष के लिए 2014–15 के नियमित आम बजट में व्यवस्था की जाएगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया

20 फरवरी 2014 को शास्त्रीय भाषाकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान की.

शास्त्रीय भाषा घोषित की गई भाषाओं के अंतर्गत निम्न लाभ दिए जाते हैं –

- संबंधित भाषा में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान.
- शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टषता केंद्र स्थापित किया जा सकता है.
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निवेदन

किया जा सकता है कि कम से कम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषाओं में विशेषज्ञता प्राप्त शोधार्थियों के लिए शास्त्रीय भाषाओं की कुछ निश्चित सीटें शुरू की जाएं.

यह मांग की जा रही थी कि उड़िघ्या, जो कि सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और जिसकी हिन्दी, संस्कृत, बंगाली, तेलुगु आदि से कोई समानता नहीं है, को एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया जाए. अभी तक संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है.

उड़िया शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत की जाने वाली छठी भाषा है, जिसके समेत पांच अन्य भाषायें निम्नलिखित हैं –

शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत किये जाने का वर्ष

उड़िया	2014
मलयालम	2013
कन्नड़	2008
तेलूगु	2008
संस्कृत	2005
तमिल	2004

उड़िया इंडो–यूरोपियन कुल की इंडो–आर्यन शाखा से संबंधित एक भारतीय भाषा है. उड़िघ्या प्रमुख रूप से भारत के राज्य ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है. यह ओडिशा की प्रमुख आधिकारिक तथा झारखण्ड की दूसरी आधिकारिक भाषा है.

अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी

बेल्जियम में बच्चों को भी इच्छामृत्यु का अधिकार मिला

बेल्जियम की संसद ने लाइलाज बीमारी के शिकार बच्चों को इच्छामृत्यु देने के अधिकार संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है. संसद में 86 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया जबकि 44 ने इसके खिलाफ वोट दिया. 12 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. इस कानून में बच्चों की आयु सीमा तय नहीं की गई है. जैसी कि संभावना है देश के राजा विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे और तब बेल्जियम दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां किसी भी उम्र के बच्चे पर ये कघनून लागू होगा.

लाइलाज बीमारी के चलते असहनीय वेदना से जूझ रहे बच्चों के अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है. इसमें अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी.

विधेयक के विरोधियों का तर्क था कि बच्चे इतना कठिन फैसला नहीं ले सकते.

12 साल पहले बेल्जियम ने लाइलाज बीमारी के शिकार वयस्कों के लिए इच्छामृत्यु का कानून बनाया था.

बेल्जियम के उत्तरी पड़ोसी देश नीदरलैंड में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इच्छामृत्यु का कानून है, बशर्ते अभिभावकों की सहमति हो.

डच शर्तों के मुताबिक, एक मरीज की इच्छामृत्यु को डॉक्टर तभी पूरा कर सकता है जबकि अनुरोध स्वैच्छिक हो और इस पर व्यापक सोच–विचार किया गया हो. मरीज का कष्ट बर्दाश्त करने की हद से परे हो और उसकी स्थिति में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं हो.

इस कानून के समर्थकों का कहना है कि अभ्यास में ये कघनून बहुत ही कम संख्या में उन क्लिक करें बच्चों पर असर डालेगा, जो अपने किशोरवय में होंगे.

कानून में व्याख्या की गई है कि बच्चा लाइलाज बीमारी का शिकार होगा, असहनीय शारीरिक दर्द से गुजर रहा होगा और बार–बार मृत्यु का अनुरोध कर होगा–तभी इच्छामृत्यु पर विचार किया जाएगा.

ये फैसला लेने से पहले अभिभावकों, डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट का सहमत होना जरूरी होगा. हालांकि विरोधियों ने इस बदलाव के खिलाफ राजनीतिज्ञों को लामबंद किया था.

चर्च के नेताओं ने इस कानून को अनैतिक बताया है.

ब्रसेल्स के आर्कबिशप एंद्रे जोसेफ, जो बेल्जियम में कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं, कहते हैं, *कानून कहता है कि किशोर आर्थिक और भावनात्मक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले सकते, लेकिन अचानक वो इस योग्य कैसे हो गए कि ऐसा फैसला ले सकें कि कोई उन्हें मृत्यु दे दे.* ये बात उन्होंने पिछले सप्ताह एक प्रार्थना सभा में कही.

कुछ बाल चिकित्सक चेतावनी दे चुके हैं कि बीमारी से त्रस्त बच्चे जोखिम में आ सकते हैं और ये सवाल लाजिमी है कि क्या एक बच्चे से वास्तव में ऐसे कठिन फैसले की अपेक्षा की जा सकती है.

पिछले सप्ताह देश के 160 बाल चिकित्सकों ने इस कानून के खिलाफ खुला पत्र दिया था. उनका दावा था कि इसकी कोई तुरंत जरूरत नहीं थी और आधुनिक दवाएं दर्द को काफी हद तक घटाने में सक्षम हैं.

लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक कैथोलिक बहुलता वाले बेल्जियम में लोग इस बदलाव के समर्थन में हैं.

बच्चों के लिए इच्छामृत्यु की शर्तें

मरीज को पूरे होशोहवाश में फैसला ले
इसके लिए अभिभावकों और मेडिकल टीम की मंजूरी होनी चाहिए
बीमारी लाइलाज होनी चाहिए
मरीज का दर्द असहनीय हो और इसे दूर करने के लिए कोई दवा मौजूद न हो

सुशील कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री निर्वाचित

महज तीन साल पहले सुशील कोइराला ने देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस की कमान संभाली थी और अब वे देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं.

कोइराला का राजनीतिक अनुभव करीब छह दशक पुराना हो चुका है और वे उन चुनिंदा राजनीतिज्ञों में शामिल हैं जो साफ सुथरी राजनीति में यकीन रखते हैं. वे सामान्य जीवनशैली के लिए भी जाने जाते हैं.

वैसे सुशील कोइराला अपनी युवावस्था में हॉलीवुड में हीरो बनने का सपना देखा करते थे. लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था. अब 75 साल की उम्र में उन्हें नेपाल के अधूरे संविधान को पूरा करने के लिए किसी हीरो के माफिक ही काम करना होगा.

प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद कोइराला ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता नेपाल के संविधान को पूरा करने की होगी.

उनका जन्म नेपाल के कोइराला परिवार में हुआ था जिसकी प्रतिष्ठा ठीक उसी तरह की है जैसी पाकिस्तान में भुट्टो या फिर भारत में गाँधी परिवार की है.

युवावस्था में ही राजनीति में उनकी दिलचस्पी पैदा हो गई थी. गिरजा प्रसाद कोइराला की मां उनकी मौसी थीं.

गिरिजा प्रसाद कोइराला और नेपाली राजनीति की दूसरी अजीम शख्सियत बीपी कोइराला से नजदीकी के चलते वे लोकतांत्रिक आंदोलन में शामिल हो गए.

21 साल की उम्र में उन्हें भारत में निर्वासित जीवन बिताना पड़ा. यह वह दौर था जब किंग महेंद्र ने देश के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री बीपी कोइराला को 1960 में बर्खास्त कर दिया था. उन्होंने निर्वासन के 20 साल भारत में गुजारे.

बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला, इन तीनों को भारतीय जेलों में भी समय बीतना पड़ा – जब इन्हें नेपाल की शाही सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक नेपाली विमान को हाईजैक करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था.

कोइराला अविवाहित जीवन व्यतीत करते रहे हैं. वे कई बार नेपाली सांसद बने. लेकिन हर बार उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया. गिरिजा प्रसाद कोइराला ने तो 1990 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें उपप्रधानमंत्री पद की पेशकश भी की थी.

इतना ही नहीं नेपाल के इस प्रधानमंत्री का अपना कोई घर तक नहीं है, नेपाली राजनीति में यह किसी अचरज से कम नहीं है. सुशील कोइराला काठमांडू में अपने रिश्तेदारों के घर ही रहते रहे.

गिरिजा प्रसाद कोइराला की 2010 की मौत के बाद सुशील किराए के मकान में रहने चले गए.

जब गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे और वोनेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तब सुशील उनके निकट सहयोगी की भूमिका निभाते रहे. हालांकि उन्होंने तब कोई भी लाभ का पद नहीं लिया था. इसके लिए उनकी आलोचना भी होती रही कि वे सिर्फ डार्क रूम राजनीति में दिलचस्पी लेते रहते हैं.

हालांकि उनकी आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं कि गिरिजा प्रसाद कोइराला की वजह से उन्हें पार्टी में इतना रूतबा हासिल था. लेकिन हकधिकघ्त यही है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में जो पार्टी पहले संविधान सभा चुनाव में 2008 में दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी वह सुशील कोइराला के नेतृत्व में पहले स्थान पर आ गई.

उनके पास मौका है कि वे अपने राजनीतिक गुरु गिरिजा प्रसाद कोइराला द्वारा शुरू किए गए नए संविधान की प्रक्रिया को पूरा कर सकें.

वैसे सुशील कोइराला एक बार नेपाल में पंचायती दल विहीन सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चला चुके हैं लेकिन अब वे कहते हैं कि महात्मा गाँधी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं.

युगांडा के राष्ट्रपति ने एंटी–गे बिल पर हस्ताक्षर किया

युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने एंटी–गे बिल पर 24 फरवरी 2014 को हस्ताक्षर किया. इसमें समलैंगिक गतिविधियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है.

युगांडा में समलैंगिकता पहले से ही अवैध है. इस नए बिल में पहली बार समलैंगिकता के दोषी को 14 साल की कैद और दूसरी बार इसका दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

यह कानून युगांडा के भीतर या बाहर के किसी भी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संगठन द्वारा समलैंगिक रिश्तों को बढ़ावा और मान्यता देने की प्रक्रिया को अवैध बनाता है. पहली बार इस कानून के जरिए समलैंगिक महिलाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है.

इस कानून में समलैंगिकों के खिलाफ शिकायत न करने को अपराध माना गया है.

इस कानून के लागू होने के बाद समलैंगिकों को गुप्त जीवन जीने को मजबूर होना पड़ेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री जॉन एफ कैरी ने इस कानून को नैतिक रूप से गलत बताते हुए कहा है कि ऐसा कर युगांडा सभी से एक कदम और पीछे चला जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका युगांडा के इस कदम से बहुत निराश है और चाहता है कि युगांडा की सरकार इस कानून को वापस ले.

अंतरराष्ट्रीय लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस एंड इंटरसेक्स एसोसिएशन या आईएलजीए ने लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स लोगों (एलजीबीटीआई) के खिलाफ आपराधिक कानूनों वाले 78 (वास्तविक संख्या 83 है) देशों की सूची बनाई गई है.

जनवरी 2014 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने एक कानून पर दस्तखत किए थे जिसके मुताबिक समलैंगिकता पर रोक लगाया जाना और एक ही लिंग के संघ में प्रवेश करने के जुर्म में 14 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान था. इसमें गे क्लब या संगठन चलाने वालों को 10 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है.

भारत में, समलैंगिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत की जाने वाली कार्रवाई पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को 11 दिसंबर 2013 को निरस्त कर दिया था. इसलिए भारत समलैंगिकता विरोधी कानून वाले देशों की मुख्य सूची में फिर से शामिल हो चुका है.

भारत और विश्व

भारत और कनाडा ने तीन समझौता–ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

24 फरवरी 2014 को भारत और कनाडा ने स्वास्थ्य, ऑडियो–विजुअल सह–निर्माण और कौशल–विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए तीन समझौता–ज्ञापनों (मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंगध्एमओयू) पर हस्तक्षर किए. इस समय कनाडा के गवर्नर–जनरल डेविड जोंसटन 22 फरवरी से 2 मार्च 2014 तक भारत के नौ–दिवसीय दौरे पर हैं. वर्ष 1998 के बाद से कनाडा के किसी गवर्नर–जनरल की यह पहली भारत–यात्रा है. भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और डेविड जोंसटन के बीच नई दिल्ली में हुई वार्ता के बाद इन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

समझौते के मुख्य बिंदु

- बायोटेक्नोलॉजी विभाग और ग्रैंड चौलेंजेज कनाडा के बीच हुआ समझौता–ज्ञापन वैश्विक स्वास्थ्य–चुनौतियों, विशेषकर महिला और बाल हेल्थकेयर की चुनौतियों का समाधान करेगा.
- ऑडियो–विजुअल सहयोग के समझौता–ज्ञापन का उद्देश्य फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में सह–निर्माण करना है. इस समझौता–ज्ञापन से भारत और कनाडा के फिल्म–निर्माता फिल्म–निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए एक मंच का प्रयोग कर सकेंगे. इस समझौते से दोनों देशों के फिल्म–उद्योगों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच संबंध गहरे होने की आशा है, जिससे सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो सकेगा. समझौते पर सूचना और प्रसारण सचिव बिमल जुल्का तथा भारत में कनाडा के उच्चायुक्त स्टीवर्ट बेक ने हस्ताक्षर किए.
- कौशल–विकास के समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत दो संगठन नामतरू राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और एसोसिएशन ऑफ कनाडियन कम्युनिटी कॉलेज फॉर स्किल डेवलपमेंट आदान–प्रदान और ज्ञानार्जन में सहयोग करेंगे.
- भारत सरकार द्वारा ऑडियो–विजुअल सह–निर्माण के क्षेत्र में किए गए इस प्रकार के अन्य समझौते
  - ☐ वर्ष 2005 में इटली सरकार से समझौता किया.
  - ☐ वर्ष 2005 में भारत सरकार ने इसी तरह के समझौते यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार से किए.
  - ☐ वर्ष 2007 में उसने जर्मनी और ब्राजील से समझौता किया.
  - ☐ वर्ष 2010 में फ्रांस के साथ समझौता किया.
  - ☐ वर्ष 2011 में न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया.
  - ☐ वर्ष 2012 में पोलैंड और स्पेन के साथ समझौता किया.

अर्थव्यवस्था/वाणिज्य

राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी

20 फरवरी 2014 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 12वीं योजना में निर्धारित कुल 13,000 करोड़ रुपये में से 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के लिए वित्तीय सहायता का स्रोत योजना व्यय तथा मनरेगा गतिविधियों, सीएएमपीए और एनएपी को मिलाने के जरिए जुटाया जाना है.

राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के तहत आवश्यक व्यय का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर राज्य सरकार 10 प्रतिशत वहन करेंगी. हालांकि, शेष सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत खर्च करेगी.

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस मिशन के उद्देश्यों में वनध्वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि करना और वन क्षेत्र की गुणवत्ता दो से बढ़ाकर आठ मिलियन हेक्टेयर करना, जैवविविधता, हाइड्रोलॉजिकल सेवाओं के साथ पारिस्थितिकीय सेवाओं में सुधार, वन में एवं आसपास रहने वाले परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि तथा वार्षिक कार्बन डाइ आक्साइड पृथक्करण में वृद्धि करना शामिल है.

यह मिशन योजना बनाने और निर्णय लेने, कार्यान्वयन और निगरानी में व्यावहारिक धरातल पर काम करने वाले संगठनों की विकेंद्रीकृत भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा. गांव स्तर पर ग्राम सभा तथा जेएफएमसी सहित ग्राम सभा के जनादेश से बनाई गई समितियां कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया गया

21 फरवरी 2014 को भारत ने ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) प्रक्षेपण परिसर –3 से स्वदेश में विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफलतापूर्वक परीक्षण किया.

परीक्षण के दौरान प्रक्षेपण परिसर द्वितीय से दागे गए मिसाइल ने एक उड़ती वस्तु पर निशाना साधा जिसे पायलटरहित लक्ष्य विमान ने समुद्र से एक निश्चित ऊंचाई पर टिका रखा था. आकाश मिसाइल का पिछला परीक्षण उसी बेस से 6 जून 2012 को किया गया था और अगले कुछ दिनों में और ऐसे ही परीक्षण किए जाने की संभावना है.

आकाश का विकास भारत में हुआ है और यह सभी मौसम में सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की (एसएएम) मिसाइल है. यह बहु दिशा और बहु लक्ष्य क्षेत्र रक्षा प्रदान करती है. मिसाइल को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित किया गया है.

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत वर्ष 1983 से 2007 के मध्य नाग, अग्नि, त्रिशूल मिसाइल और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल सहित मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित की गई.

- इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है और इस रेंज में एक विमान को निशाना बनाने की क्षमता है.
- यह अपने साथ 50 किलोग्राम परमाणु सामग्री ले जाने में सक्षम है.
- इसमें एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और हमला करने के लिए एक बैटरी भी है. प्रत्येक आकाश बैटरी में चार 3डी निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे (पेसा) रडार है.
- इसमें 12 मिसाइलों के साथ चार स्वचालित लांचर शामिल हैं जो आपस में जुड़े है.
- इसमें बैटरी स्तर रडार, राजेंद्र रडार भी है और एक बैटरी नियंत्रण केंद्र है. इसी के साथ वह रास्ते में आने वाले कई लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें भी भेद सकती है.
- मिसाइल में आत्म विनाशकारी उपकरण भी लगा है.
- इसमें लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को निष्प्रभावी बनाने की क्षमता है.
- इस मिसाइल की तुलना रक्षा विशेषज्ञों ने सतह से हवा में मार करने वाली अमेरिकी एमआईएम–104 पैट्रिएट मिसाइल से की है.

Develop India

Online Subscription

Read

Develop India

पर्यावरण/पारिस्थितिकी

इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार–2010

19 फरवरी 2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्री डॉ. एम वीरप्पा मोइली ने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार–2010 प्रदान किए. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार–2010 के तहत दो पुरस्कार श्संगठनश वर्ग में और तीन पुरस्कार श्वैयक्तिकश वर्ग में दिया गया.

जाट रेजीमेंट की 21वीं बटालियन को पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया. रेजीमेंट ने श्गो–ग्रीनश अभियान के तहत असम के ढुबरी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित इलाकों में वृक्षारोपण का काम किया था.

दक्षिण सुंदरबन के जॉयगोपालपुर गांव के कुछ युवाओं द्वारा शुरू किए गए जॉयगोपालपुर ग्राम विकास केंद्र को पर्यावरण संरक्षण और जन जागरण के लिए पुरस्कृत किया गया.

1992 में स्थापित एक गैर–सरकारी संगठन श्साथीश को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के घिन्नी–घाट क्षेत्र में पर्यावरण उन्नयन तथा सामाजिक विकास के लिए पुरस्कृत किया गया.

संगठन के वर्तमान निदेशक डॉ. अनिल शर्मा हैं, जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया.

1998 में स्थापित गैर–सरकारी संगठन श्वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडियाश के सह संस्थापक और अध्यक्ष कार्तिक सत्यनारायणन को वन्यजीव संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया.

पुद्दुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति में इंजीनियर डॉ. एन. रमेश को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया.

पुरस्कार/सम्मान

अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार

15 फरवरी 2014 को वर्ष 2013 का अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार भारत के डॉ विजयकुमार विनायक डोंगरे (वीवी डोंगरे) और चीन के प्लास्टिक सर्जन प्रो. गुओचेंग झांग को प्रदान किया गया. उन्हें यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया. उन्हें यह पुरस्कार उपचार, प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से कुष्ठ रोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने एवं इस रोग के उन्मूलन के लिए दिया गया.

अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना गाधी स्मारक कुष्ठ फाउंडेशन (Gandhi Memorial Leprosy Foundation) ने वर्ष 1950 में की थी. इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग के प्रति महात्मा गांधी की सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है. यह पुरस्कार कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में व्यक्तियों और संस्थाओं के सराहनीय योगदान को मान्यता देता है.

यह पुरस्कार प्रति दूसरे वर्ष कुष्ठ रोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए व्यक्तियों ६ संस्थाओं को दिया जाता है.

कुष्ठरोग (स्मचतवेल) या हैन्सेन का रोग (Hansen's Disease), चिकित्सक गेरहार्ड आर्मोर हैन्सेन के नाम पर, माइकोबैक्टेरियम लेप्री (Mycobacterium leprae) और माइकोबैक्टेरियम लेप्रोमेटॉसिस (Mycobacterium lepromatosis) जीवाणुओं के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है. कुष्ठरोग मुख्यतः ऊपरी श्वसन तंत्र के श्लेष्म और बाह्य नसों की एक ग्रैन्युलोमा–संबधी (हतंदनसवउंजवने) बीमारी हैय त्वचा पर घाव इसके प्राथमिक बाह्य संकेत हैं. यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए, तो कुष्ठरोग बढ़ सकता है, जिससे त्वचा, नसों, हाथ–पैरों और आंखों में स्थायी क्षति हो सकती है.

एम. लेप्रोमेटॉसिस (M- lepromatosis) पहचाना गया अपेक्षाकृत नया माइकोबैक्टेरियम है, जिसे 2008 में विकीर्ण लेप्रोमेटस कुष्ठरोग के एक जानलेवा मामले से पृथक किया गया था.

इजरायली राष्ट्रपति उत्कृष्टता पदक

जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को इजरायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेस ने येरुशलम में इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजरायली राष्ट्रपति उत्कृष्टता पदक 25 फरवरी 2014 को प्रदान किया. उन्हें यह सम्मान इजरायल की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के साथ–साथ शिक्षा के माध्यम से यहूदी–विरोधी और नस्लवाद–विरोधी भावना से लड़ने के लिए दिया गया.

एंजेला मार्केल को उत्कृष्टता पदक इजरायली राष्ट्रपति शिमोन पेरेस ने प्रदान किया. पुरस्कार समारोह के दौरान मार्केल अपने मंत्रिमंडल के 16 सदस्यों के साथ इजरायल की 24 घंटे की यात्रा पर थीं.

राष्ट्रपति द्वारा इजरायली राष्ट्रपति पदक प्रति वर्ष देश को असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है.

यहूदी विरोधी भावना (एंटी–सेमिटिज्म) एक धार्मिक या नस्लीय समूह के रूप में यहूदियों के प्रति एक विद्वेषपूर्ण विश्वास या व्यवहार है. यह शब्द 1879 में जर्मन आंदोलनकारी विल्हेम मार ने उस समय मध्य यूरोप में चल रहे यहूदी विरोधी अभियानों को नाम देने के लिए गढ़ा था. एंटी–सेमेटिज्म का दृष्टिकोण रखने वाला एंटी–सेमाइट कहलाता है.

राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2012–13

18 फरवरी 2014 को सिक्किम राज्य को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2012–13 प्रदान किया गया. मानव संसाधन विकास मंत्री शशि थरूर ने यह पुरस्कार सिक्किम के पर्यटन मंत्री भीम दुंगल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया.

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषणा की. मंत्रालय ने सिक्किम का वर्णन समृद्ध संस्कृति और सुंदर प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में किया.

पुरस्कार समारोह में भीम दुंगल ने ये सूचित किया की सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने कई आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है.

सिक्किम के पर्यटन विभाग ने केरल , गुजरात, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों के साथ करार किया था . राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए विभाग भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है.

पर्यटन मंत्रालय राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने तथा देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियों, राज्य्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र की गतिविधियों का समन्वय करने हेतु नोडल एजेंसी है. मंत्रालय का नेतृत्व केन्द्रीय पर्यटन मंत्री करते हैं और राज्य मंत्री उनका सहयोग करते हैं.

64वें बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

मराठी फिल्म **किल्ला** को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए क्रिस्टल बेअर (ग्लासेर्नन बार) पुरस्कार 17 फरवरी 2014 को दिया गया. यह पुरस्कार 64वें बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में जेनरेशन केप्लस सेक्शन में चिल्ड्रंस जूरी द्वारा प्रदान किया गया. फिल्म किल्ला अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित है.

फिल्म को पुरस्कार प्रदान करने का उल्लेख करते हुए जूरी ने कहा कि फिल्म आव्रजन (माइग्रेशन) के सार्वभौमिक द्वंद्व और लोगों, विशेषकर बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का चित्रण करती है और भारत की खोज के लिए प्रेरित करती है. फिल्म किल्ला ने अच्छे कैमरा–वर्क और श्रेष्ठ अभिनेताओं सहित सभी पहलुओं से जूरी को संतुष्ट किया.

बर्लिनाले के पूरे इतिहास में किल्ला चुनी जाने वाली तीसरी मराठी और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है.

फिल्म किल्ला का निर्माण मधुकर आर मुसले, अजय जी राय और एलन मैकएलेक्स ने किया. इसका निर्माण जार पिक्चर्स के बैनर–तले किया गया और इसका प्रस्तुतीकरण एम आर फिल्मवर्क ने किया. सनडांस फिल्म समारोह 2014 में वर्ल्ड ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन सेक्शन में चुनी जाने वाली जार पिक्चर्स की एक अन्य फिल्म थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत लायर्स डाइस.

अविनाश इस समय निशिकांत कामत की इरफान खान स्टारर अगली फिल्म के फोटोग्राफी–निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं.

किल्ला आव्रजन (माइग्रेशन) के सार्वभौमिक द्वंद्व और लोगों, मुख्यतः बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का चित्रण करती है. फिल्म की कहानी चीनू नामक एक बच्चे के इर्द–गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की मौत के बाद नए माहौल में सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस करता है.

पुस्तकें

- *''लेवरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी इन साउथ एशिया''*
- *''हिंदू धर्म पर लिखी विवादास्पद वेंडी डोनीगर की किताब 'द हिंदूज : एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री''*

"लेवरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी इन साउथ एशिया"

भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में ***"लेवरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी इन साउथ एशिया"*** नामक पुस्तक का विमोचन 6 फरवरी 2014 को किया. इस पुस्तक का संपादन रशपाल सिंह, सुचा सिंह गिल और नीतू गौर ने किया.

पुस्तक ग्रामीण अनुसंधान और औद्योगिक विकास केंद्र (सीआरआरआईडी), चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है. इसमें दक्षिण एशिया के उन विशेषज्ञों के चुने गए पेपरों का संकलन है जिन्होंने मार्च 2013 में आयोजित सीआरआरआईडी के सम्मेलन में हिस्सा लिया था. इस किताब में राजनयिकों, शिक्षाविदों और व्यापारियों के योगदान को भी शामिल किया गया है. इसमें दक्षिण एशियाई देशों के बीच समृद्धि के बंटवारे पर भी विचार व्यक्त किया गया है.

"हिंदू धर्म पर लिखी विवादास्पद वेंडी डोनीगर की किताब 'द हिंदूज : एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री"

पेंगुइन इंडिया हिंदू धर्म पर लिखी गई एक अमरीकी लेखक की पुस्तक को वापस लेने और उसकी बाकी बची प्रतियों को नष्ट करने के लिए सहमत हो गई है. दिल्ली के साकेत में निचली अदालत में दोनों पक्षों के बीच हुए करार को मंजूरी दे दी गई.

वेंडी डोनीगर की किताब 'द हिंदूज : एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री' को ये कहते हुए कानूनी रूप से चुनौती दी गई है कि इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लगी है.

रिपोर्टों के अनुसार प्रकाशन कंपनी पेंगुइन इंडिया और शिक्षा बचाओ आंदोलन संगठन के बीच इस पुस्तक को लेकर समझौता हो गया है. हालांकि अभी तक पेंगुइन इंडिया की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

इस विवादास्पद किताब को दो साल पहले रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया था और बीते चार बरसों से ये किताब बिक रही है और तभी से इसके खिलाफ अभियान भी चल रहा है.

इस किताब के खिलाफ दस हजार से ज्यादा लोग एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. इसमें दावा किया गया है कि किताब में बहुत सी तथ्यात्मक गलतियां हैं.

शिक्षा बचाओ आंदोलन ने 2011 में पेंगुइन इंडिया के खिलाफ ये कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि ये किताब हिंदुओं का अपमान करती है क्योंकि इसमें हिंदुओं की श्स्थापित धार्मिक मान्याताओं के विपरीत बातें कही गई हैं.

किताब के मुख्य पृष्ठ पर छपी तस्वीर तो आपत्तिजनक है ही, साथ ही किताब में देवी देवताओं और महापुरुषों के बारे में भी ओछी टिप्पणियां की गई हैं. पूरे समाज की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है. हमने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है."

वहीं संगठन की वकील मोनिका अरोड़ा ने रॉयटर्स को बताया, "उन्होंने हिंदू देवताओं और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपमानजनक बातें कही हैं."

इस बीच लेखिका वेंडी डोनिगर ने फेसबुक पर जारी एक बयान में कहा, मुझे समर्थन में जो मैसेज मिले हैं मैं उनसे खुश हूं. मुझे भारत से भी कई लोगों ने मैसेज भेजे हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिली लेकिन उन्होंने मेरी किताब पढ़ी है.

उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं. लेकिन मैं इसके लिए पेंगुइन इंडिया को जिम्मेदार नहीं मानती हूं क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया. मुझे खुशी है कि इंटरनेट के इस दौर में किसी किताब पर पाबंदी लगाना सभंव नहीं है.

शिक्षा बचाओ आंदोलन का कहना है कि वो इस फैसले से खुश हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि ये फैसला 'अनुचित' है और किताब 'किसी भी तरह से ईशनिंदक' नहीं है.

किताब वापस लिए जाने से साहित्यकार और लेखक खासे नाराज हैं. जाने माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी का कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है.

वाजपेयी कहते हैं, दीनानाथ बत्रा पूरे समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं. लोग अपनी मर्जी से पढ़ें, जिसे नहीं पढ़ना है वो न पढ़े. मगर प्रतिबंध या रोक अच्छी बात नहीं है."

भारत में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर खासी आलोचना हो रही है. कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि धार्मिक संगठन देश में अभिव्यक्ति और कलात्मक स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगा रहे हैं.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस खब्बर को 'बेहद निराशाजनक' कहा है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "अगर किसी को कोई किताब पसंद नहीं आती है तो उसका जवाब है एक और किताब. न कि उस पर प्रतिबध, या कानूनी कार्रवाई या मार पिटाई की धमकी." वहीं साहित्यकार उमा वासुदेव मानती हैं वह किताबों पर किसी भी तरह के प्रतिबंध के पक्ष में तो नहीं हैं लेकिन लेखकों

को भी चाहिए कि वे धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं.

समझौते के अनुसार अब पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस किताब को देश भर में दुकानों से वापस लेना है.

लेकिन इंटरनेट विशेषज्ञ प्रशांतो कुमार रॉय का कहना है कि इंटरनेट पर इसके प्रसार को रोक पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि समझौते के बाद से ही इंटरनेट पर किताब की पीडीएफ फाइलों का प्रसार बढ़ रहा है. वह कहते हैं कि इंटरनेट के दौर में इसका प्रसार रोका नहीं जा सकता है. जब कोई किताब विवादास्पद हो जाती है तो उसका प्रसार और बढ़ जाता है. इस किताब के साथ भी यही हुआ है. लोग इंटरनेट से इसे धड़ल्ले से डाउनलोड कर रहे हैं.

'द हिंदूज : एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री' को वापस लिए जाने के समझौते के बाद अब शिक्षा बचाओ आंदोलन विंडी डोनिगर की एक अन्य किताब पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करने लगा है.

22वां विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न

22वां विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में 23 फरवरी 2014 को संपन्न हो गया. 22वें विश्व पुस्तक मेले का मुख्य विषय "बाल–साहित्य" रखा गया. 22वें विश्व पुस्तक मेले का विशिष्ट अतिथि देश पोलैंड रहा.

पुस्तक मेले के आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट के अनुसार मेले में पिछले 9 दिनों में 10 लाख से अधिक लोग आए.

22वें विश्व पुस्तक मेले में प्रसिद्ध विद्वान डॉ. कर्ण सिंह ने अपनी निबंधों, कविताओं तथा उपन्यास संग्रह 'त्रिवेणी' का विमोचन किया.

पब्लिक ईश्यूज बिफोर पार्लियामेंट

उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने एक समारोह में सांसद विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक पब्लिक ईश्यूज बिफोर पार्लियामेंट ('Public Issues Before Parliament') का विमोचन 19 फरवरी 2014 को किया.

इस पुस्तक में विजय दर्डा ने अपनी संसदीय कार्य अवधि के दौरान किए गए महत्वपूर्ण योगदानों को प्रस्तुत किया है. यह पुस्तक आम नागरिकों को समर्पित है, जो संसद को अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के माध्यम के रूप में देखते हैं.

- विजय दर्डा को वर्ष 1998 में कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र से राज्य सभा का सांसद निर्वाचित किया गया था. उन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए राज्य सभा का सांसद निर्वाचित किया गया. ब्रिटेन में विजय दर्डा कांग्रेस पार्टी से राज्य सभा के सांसद और मराठी समाचार पत्र "लोकमत" (Marathi newspaper Lokmat) मीडिया समूह के अध्यक्ष हैं.
- विजय दर्डा को ब्रिटेन में अंतरराष्ट्रीय न्यायविद् पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें यह पुरस्कार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी शिक्षा के प्रसार में मौलिक भूमिका निभाने के लिए दिया गया.

सम्मेलन/समारोह

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के विदेश मंत्रियों की 35वीं बैठक

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के विदेश मंत्रियों की 35वीं बैठक 20 फरवरी 2014 को मालदीव के बंदोस द्वीप रिजॉर्ट में संपन्न हुई. इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने व्यापक संस्थागत और संरचनात्मक सुधारों की अपील की. उन्होंने सार्क और पर्यवेक्षक देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत पर बल दिया.

निम्नलिखित नौ देशों को पर्यवेक्षक के रूप में सार्क में शामिल किया गया– ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरीशस, म्यांमार, अमेरिका.

सार्क बैठक के अवसर पर सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री, सरताज अजीज से भी मुलाकात की.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी. इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है. अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवां सदस्य बन गया. पहली बार शिखर सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में आयोजित किया गया.

सार्क के सदस्य देश हैं – बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान

प्रेक्षक देश

- ऑस्ट्रेलिया
- चीन
- यूरोपीय संघ
- ईरान
- जापान
- मॉरिशस
- म्यान्मार
- दक्षिण कोरिया
- संयुक्त राज्य अमेरिका

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.5 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है।

1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। मई 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार फिर रखा गया था। अप्रैल 1981 में सातों देश के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। इनकी समिति ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए पाँच व्यापक क्षेत्रों की पहचान की। सहयोग के नए क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में जोड़े गए।

संगठन के उद्देश्य

- दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जीवन की उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए
- क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिएय
- दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने और मजबूत प्रदान करने के लिएय
- आपसी विश्वास, एक दूसरे समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिएय
- आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिएय
- अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिएय
- आपस में साझा हित के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने के लिए, और
- समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए।

महासचिव

- बांग्लादेश के अबुल अहसान 16 जनवरी, 1987 से 15 अक्टूबर, 1989
- भारत के कांत किशोर भार्गव 17 अक्टूबर, 1989 से 31 दिसंबर, 1991
- मालदीव के इब्राहिम हुसैन जाकी 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर, 1993
- नेपाल के यादव कांत सिलवाल 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसंबर, 1995
- पाकिस्तान के नईम यू हासन 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसंबर, 1998
- श्रीलंका के निहाल रोडरिगो 1 जनवरी, 1999 से 10 जनवरी, 2002
- बांग्लादेश के क्यू.ए.एम.ए. रहीम 11 जनवरी, 2002 से 28 फरवरी, 2005
- भूटान के ल्योपनो चेन्क्याब दोरजी 1 मार्च, 2005 से 29 फरवरी, 2008
- भारत के शील कांत शर्मा 1 मार्च, 2008 से अबतक

जी–20 समूह देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक सिडनी में संपन्न

23 फरवरी 2014 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जी–20 समूह देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गर्वनरों की दो दिवसीय बैठक समाप्त हुई. इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भाग लिया.

जी–20 समूह देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गर्वनरों की इस बैठक में अगले पांच वर्ष के दौरान सभी सदस्य देशों की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दो प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करने का फैसला किया गया. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटा सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका को समर्थन देने का भी फैसला किया गया.

जी–20 समूह देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गर्वनरों की यह बैठक अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के इस अनुमान की पृष्ठभूमि में आयोजित की गयी कि वैश्विक विकास दर अगले साल बढ़कर चार प्रतिशत हो जाएगी, जो कि वर्ष 2013 में 3.7 प्रतिशत थी.

जी–20 समूह देशों की इस बैठक में भाग लेने के पश्चात वित्तमंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, "जी–20 बैठक में अमरीका में वित्तीय प्रोत्साहन कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष कोटा सुधारों के बारे में भारत की चिन्ताओं को दूर किये जाने पर समति बनी है और मैं इस दो दिन की बैठक के नतीजों से संतुष्ट हूं."

पदत्याग/पदमुक्त

- एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी
- रिशांग कीशिंग
- एन किरण कुमार रेड्डी

एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी

एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी (डीके जोशी) ने नौसेना पनडुब्बी आईएनएस सिन्धुरत्न में हुए हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नौसेना अध्यक्ष पद से 26 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया.

नौसेना प्रमुख ने यह कदम आईएनएस सिधुरत्न में विस्फोट के बाद धुआं फैलने से सात जवानों के बेहोश होने और दो के लापता होने के कुछ ही घंटों के बाद उठाया. भारत सरकार ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया. एडमिरल डीके जोशी को 31 अगस्त 2012 को नौसना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. एडमिरल डीके जोशी आजादी के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा देने वाले पहले रक्षा बल प्रमुख है.

रूस निर्मित किलो क्लास पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न मुंबई बंदरगाह से 90 नॉटिकल मील की दूरी पर दुर्घटना ग्रस्त हो गई. उस समय आईएनएस सिंधुरत्न अभ्यास पर थी. आईएनएस सिंधुरत्न को नौ सेना में वर्ष 1988 में शामिल किया था.

सिंधु श्रेणी की पनडुब्बियों को भारत सरकार ने रूस से प्राप्त किया. आईएनएस सिन्धुरत्न, सिन्धुरक्षक श्रेणी की पनडुब्बी है. जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल प्रतिरक्षा या युद्धक परिस्थितियों में किया जा सकता है. इस श्रेणी की अन्य पनडुब्बियां रूस के सहयोग से निर्मित की गई हैं. जिनमें सिन्धुरत्न के अलावा सिन्धुघोष, सिन्धु/वज, सिन्धुराज, सिन्धुवीर, सिन्धुकेसरी, सिन्धुविजय और सिन्धुशस्त्र शामिल है. इनमें सिन्धुशस्त्र सबसे आधुनिक पनडुब्बी है जिसे वर्ष 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. 300 मीटर गहराई तक गोता लगानेवाली इन पनडुब्बियों से तारपीडो मिसाइलें दागी जा सकती हैं.

एन किरण कुमार रेड्डी

एन किरण कुमार रेड्डी (नल्लारी किरण कुमार रेड्डी) ने आंध्र प्रदेश के विभाजन के निर्णय के विरोध में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस पार्टी से 19 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया. एन किरण कुमार रेड्डी ने अपना इस्तीफा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन को सौंपा.

एन किरण कुमार रेड्डी ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया.

एन किरण कुमार रेड्डी (नल्लारी किरण कुमार रेड्डी) ने आन्ध्रप्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ 25 नवंबर 2010 को ली थी. एन रेड्डी ने के रोसैया का स्थान लिया. एन किरण कुमार रेड्डी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के पहले आन्ध्रप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे. किरण कुमार रेड्डी चित्तूर जिले के पिलेरू क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक और रायलसीमा क्षेत्र के निवासी है.

विदित हो कि आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना को 29वां राज्य बनाने संबंधी विधेयक 18 फरवरी 2014 को लोकसभा में पारित हो गया.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्रप्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य के गठन संबंधी मसौदा विधेयक को 5 दिसंबर 2013 को

भारत के वयोवृद्ध सांसद रिशांग कीशिंग का राजनीति से संन्यास

भारत के 94 वर्षीय वयोवृद्ध सांसद रिशांग कीशिंग ने 21 फरवरी 2014 को संन्यास लेने का फैसला किया. वर्ष 1952 में समाजवादी पार्टी से निर्वाचित होने के बाद वे पहले लोकसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में आए थे. उन्होंने सात दशकों तक देश की सेवा की. साल 1962 में वे कांग्रेस में शामिल हुए थे.

राज्य सभा में रीशांग कीशिंग का वर्तमान कार्यकाल अप्रैल 2014 में खत्म होना है. अभी तक वे चार बार मणिपुर के मुख्यमंत्री, राज्य सभा में दो कार्यकाल और लोकसभा में दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. कीशिंग एक शिक्षक और वे नागा बहुल इलाके उखरुल जिले के मूल निवासी हैं.

मंजूरी प्रदान की थी. तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी मसौदा विधेयक को मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) ने तैयार किया.

तेलंगाना राज्य में हैदराबाद सहित दस जिले होंगे. हैदराबाद 10 वर्ष के लिए दोनों राज्यों (तेलंगाना और सीमांध्र) की संयुक्त राजधानी होगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य बनाने के तौर–तरीकों को तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) 3 अक्टूबर 2013 को गठित करने का फैसला किया था. मंत्रिसमूह (जीओएम) को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे.

निर्वाचित/नियुक्त

- *सत्य नडेला*
- *मत्तेओ रेंजी*
- *इब्राहीम महलाब*
- मत्तेओ रेंजी

सत्य नडेला

भारतीय मूल के अमेरिकी एग्जेक्युटिव सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए सीईओ चुन लिए गए हैं। नडेला मौजूदा सीईओ स्टीव बॉमर की जगह लेंगे। वह माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ हैं। गौरतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के लिए पिछले पांच महीने से खोज चल रही थी।

हैदराबाद के रहने वाले नडेला माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और एंटरप्राइज ग्रुप के वाइस प्रेजिडेंट हैं। नडेला को सीईओ के रेस में सबसे आगे माना जा रहा था। क्लाउड और एंटरप्राइज ग्रुप संभालने वाले नडेला इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के 19 अरब डॉलर के सर्वर ऐंड टूल्स के हेड थे।

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व चेयरमैन रवि वेंकटेशन का कहना है कि नडेला माइक्रोसॉफ्ट में सबसे काबिल लोगों में से हैं। उनका कहना है, नडेला के पास एंटरप्राइज सेक्शन की महारत है, शायद वह कंज्यूमर ऐंड की चीजों को शायद ही अच्छी तरह हैंडल कर पाएं।

मत्तेओ रेंजी

तीन दिन तक चली रायशुमारी के बाद मत्तेओ रेंजी इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वह इटली के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटैनो को अपने मंत्रियों की सूची भेज दी है।

रेंजी की नई गठबंधन सरकार में 16 मंत्री शामिल हैं, जिनमें महिलाओं की भी बराबरी की हिस्सेदारी रखी गई है। इसके अलावा कैबिनेट में ज्यादातर युवाओं को मौका दिया गया है। नई कैबिनेट की औसत उम्र 47.8 साल है। यानि यह अब तक की सबसे युवा कैबिनेट है।

रेंजी ने नेपोलिटैनो के साथ बातचीत के बाद कहा, ष्मैं नई सरकार और राष्ट्रपति से ठोस जवाबदेही की अपेक्षा कर रही इटली की जनता का विश्वास जीतने की भरसक कोशिश करूंगा।ष

नेपोलिटैनो ने कहा कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया गया है। पहली बार मंत्री बनाए गए नए लोगों में रेंजी की छाप दिखाई देती है।

गौरतलब है, रेंजी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मार्च में श्रम सुधारों की प्रक्रिया शुरू करने से पहले नए मतदान कानून और राजनीतिक प्रणाली को सरल बनाया जाएगा। लोक–प्रशासन में सुधार अप्रैल में और वित्तीय सुधार मई में शुरू किए जाएंगे। रेंजी युवा और ऊर्जावान हैं, लेकिन सरकार चलाने के अनुभव पर सवाल उठने लगते हैं। उन्होंने कहा कि रेंजी के सामने इटली को आर्थिक संकट से उबारने समेत कई चुनौतियां हैं।

इब्राहीम महलाब

इब्राहीम महलाब ने मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में 25 फरवरी 2014 को शपथ ली. इब्राहीम महलाब ने हाजेम अल–बेबलावी का स्थान लिया. इब्राहीम महलाब हुस्नी मुबारक की राजनीतिक पार्टी के पूर्व सदस्य हैं. वह पिछले प्रशासन में आवास मंत्री थे.

इब्राहीम महलाब तानाशाह मुबारक को अपदस्थ करने वाले 2011 के विद्रोह के बाद मिस्र की छठी सरकार के मुखिया बनें.

इब्राहीम महलाब अरब कॉन्ट्रैक्टर्स के पूर्व सीईओ हैं. अरब कॉन्ट्रैक्टर्स इस क्षेत्र की सबसे बड़ी निर्माण–फर्मों में से एक है.

मत्तेओ रेंजी

मत्तेओ रेंजी ने 22 फरवरी 2014 को इटली के नये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. मत्तेओ रेंजी को इटली के राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटैनो ने शपथ दिलाई. मत्तेओ रेंजी का कार्यकाल वर्ष

2018 तक निर्धारित है.

मत्तेओ रेंजी की उम्र 39 वर्ष होने के कारण वे इटली के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गये. मत्तेओ रेंजी की कैबिनेट में कई युवा मंत्री हैं और मंत्रियों की औसत उम्र 47.8 वर्ष है.

मत्तेओ रेंजी सेंटर–लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडी) के नेता हैं और उन्होंने गठबंधन सरकार बनायी. उनकी कैबिनेट में 16 मंत्री शामिल हैं, जिनमें से आधी संख्या महिलाओं की है.

मत्तेओ रेंजी की सरकार में शामिल ज्यादातर मंत्री मध्यमार्गी–वामपंथी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं.

मत्तेओ रेंजी से पूर्व एनरिको लेट्टा इटली के प्रधानमंत्री थे. मत्तेओ रेंजी की कैबिनेट में पूर्व सरकार के तीन मंत्रियों को उनके पदों पर यथावत रखा गया है.

ओलेक्जेंडर टर्चयोनोफ

पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन की संसद ने संसद के स्पीकर ओलेक्जेंडर टर्चयोनोफ को यूक्रेन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में 23 फरवरी 2014 को नियुक्त किया. इसके पहले यूक्रेन की संसद ने महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को 22 फरवरी 2014 को उनके पद से हटा दिया.

यूरोपीय संघ और यूक्रेन व्यापार संधि को अस्वीकार करने के बाद से ही राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की राजधानी कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे विरोध–प्रदर्शन काफी तेज हो गया था. 18 फरवरी 2014 के बाद से पुलिस और जनता के बीच संघर्ष में लगभग 80 लोगों की जाने चली गई.

यूक्रेन की संसद के स्पीकर ओलेक्जेंडर टर्चयोनोफ को यूक्रेन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त के साथ ही साथ यूक्रेन की संसद ने विपक्ष की नेता यूलिया तेमोंशको को रिहा कर दिया तथा 25 मई 2014 को आम चुनाव करने की घोषणा की.

निधन/मृत्यु

- *प्रोकाश करमाकर*

प्रोकाश करमाकर

चित्रकार प्रोकाश करमाकर का उम्र संबंधी बीमारी के कारण 24 फरवरी 2014 को निधन हो गया. वह 81 वर्ष के थे. उनकी चित्रकारी ने आधुनिक भारत में व्याप्त सामाजिक विघटन और भ्रांति को प्रतिबिंबित किया.

प्रोकाश करमाकर पिकासो और 19वीं सदी के प्रभाववादी आंदोलन के प्रभाववादियों के कार्यों से प्रभावित थे. श्प्रभाववादीश शब्द 1874 में फ्रांसीसी कला–समीक्षक लुई लेरॉय ने मॉनेट की पेंटिंग पर सूर्योदय के पेंटिंग–प्रभाव के आधार पर गढ़ा था. यह शब्द मॉनेट और कई अन्य चित्रकारों द्वारा प्रयुक्त स्वच्छंद, अपरिभाषित और असमाप्त शैली का वर्णन करने के लिए सृजित किया गया था.

- प्रोकाश करमाकर वर्ष 1933 में कोलकाता (तब के कलकत्ता) में पैदा हुए थे.
- उनकी पेंटिंग्स लखनऊ और दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और कोलकाता स्थित अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जैसी प्रसिद्ध गैलरियों का अंग हैं.
- 1956 में उन्होंने गली–प्रदर्शनियाँ आयोजित करनी शुरू कीं, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और उनकी पहली प्रदर्शनी 1959 में इंडियन म्यूजियम, कोलकाता की रेलिंग्स पर लगी थी.

रुद्र कृष्णा श्रीकान्तन

कर्नाटक संगीत के गायक रुद्र कृष्णा श्रीकान्तन का बंगलौर में 17 फरवरी 2014 को निधन हो गया. वह 94 वर्ष के थे. आरके श्रीकान्तन की आत्मकथा "वाइस ऑफ जनरेशन" (टवपबम वि ळमदमतंजपवद) जनवरी 2014 में विमोचित की गई.

- रुद्र कृष्णा श्रीकान्तन का जन्म कर्नाटक के हासन जिले में 14 जनवरी 1920 को हुआ था. उनके पिता कृष्णा शास्त्री संस्कृत और वेद के विद्वान थे.

- रुद्र कृष्णा श्रीकान्तन को भारत सरकार ने वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था. बंगलौर नगर निगम द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ आध्यापक का पुरस्कार दिया गया.
- कर्नाटक सरकार ने उन्हें संगीत कला रत्न, कनक पुरंदर पुरस्कार और राज्योत्सव पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया.
- रुद्र कृष्णा श्रीकान्तन को संमुखानंद सभा, मुंबई द्वारा राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से, उत्तरी अमेरिका के कर्नाटक संगीत एसोसिएशन द्वारा संगीत सागर पुरस्कार से, त्यागराज ट्रस्ट, तिरुपति द्वारा सतपथगिरी संगीत विद्वानमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

खेल/खिलाड़ी

खेल/खिलाड़ी

- *सोची ओलंपिक का समापन*

सोची ओलंपिक का समापन

रूस के सोची में 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही संपन्न हो गए हैं. इन खेलों में मेजबान रूस पदक तालिका में शीर्ष पर रहा. 17 दिन चले खेलों के समापन समारोह की अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने की. 130 मिनट के समापन समारोह में रूस ने जमकर खर्च किया. समापन समारोह के दौरान ओलंपिक ध्वज दक्षिण कोरिया को सौंप दिया गया.

सोची में ब्रिटेन ने 26 पदकों के साथ शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की. सोची में ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले चरमपंथी हमले की आशंका और रूस के कठोर समलैंगिकता विरोधी कानूनों को लेकर प्रदर्शनों ने खेलों को लेकर मेजबान रूस की चिंता बढ़ा दी थी.

समापन समारोह में थॉमस बाक ने कहा, रूस और सोची ने अपना वादा पूरा किया और चिंताओं से ऊपर उठकर प्रभावशाली ओलंपिक खेल आयोजित किए. बाक ने कहा, यह उत्कृष्ट खेल आयोजन था और इससे खेलों के शुरू होने से पहले की गई आयोजकों की आलोचना पलट जाएगी. फिश्ट स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में अपने भाषण में बाक ने ओलंपिक के मूल मूल्यों पर जोर देते हुए कहा, ओलंपिक गाँव में एक छत के नीचे एक साथ रहकर धावकों ने सोची से दुनिया को समाज में शांति, सम्मान और सहिष्णुता का संदेश दिया है.

सोची ओलंपिक खेलों में रूस ने 13 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 33 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया. हालाँकि राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की आइस हॉकी में स्वर्ण पदक की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी.

2010 में कनाडा के वेंकोवर में हुए शीतकालीन ओलंपिक खेलों में रूस सिर्फ 15 पदक ही जीत सका था और पदक तालिका में 11वें स्थान पर था. यह रूस का शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे खराब प्रदर्शन भी था.

सोची ओलंपिक खेलों पर करीब तीस अरब पाउंड खर्च हुए और इन्हें अब तक का सबसे महंगा खेल आयोजन माना जा रहा है. सोची में 88 देशों के कुल 2800 एथलीटों ने हिस्सा लिया. इस बार युवा प्रशंसकों को जोड़ने के लिए 12 नई स्पर्धाएं ओलंपिक में जोड़ी गईं थी.

शीतकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे बड़ा डोपिंग निरोधक अभियान भी सोची में चलाया गया. ओलंपिक के दौरान कुल 2453 डोप टेस्ट किए गए जिनमें छह एथलीट टेस्ट पास करने में नाकाम रहे.

वर्ष 2015 की विश्व ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार भारत को सौंपी गई

विश्व ब्रिज फेडरेशन ने बरमूडा बाउल (पुरुष) और वेनिस कप (महिला) के लिए विश्व ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार भारत को सौंपी. विश्व ब्रिज फेडरेशन द्वारा इसकी घोषणा 17 फरवरी 2014 को की गई. विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन अक्टूबर 2015 में किया जाना है.

विश्व ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तमिलनाडु में चेन्नई और गोवा में **पणजी** को चुना गया है. इस विश्व स्पर्धा में 66 देशों के

550 खिलाड़ियों को भाग लेना है.

विश्व ब्रिज फेडरेशन (डब्ल्यूबीएफ) हर दूसरे साल विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन करता है. अंतरराष्ट्रीय ब्रिज का यह मुख्य टूर्नामेंट है, जिसमें बरमूडा बाउल ट्रॉफी के लिए हर भौगोलिक क्षेत्र की शीर्ष टीमें एक–दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं. इसके अतिरिक्त, विश्वभर से शीर्ष महिला टीम और शीर्ष वरिष्ठ टीम के लिए इसमें अलग से ट्रॉफी (क्रमशः वेनिस कप और डीओरसी ट्रॉफी) होती हैं.

- डब्ल्यूबीएफ अध्यक्ष – इटली के गिआनरिगो रोना
- भारतीय ब्रिज फेडरेशन (बीएफआई) के अध्यक्ष – एन आर किरुबकारा मूर्ति